चिंताजनक मॉनसून

इस वर्ष मॉनसून में प्रगति 12 सालों में सबसे धीमी है. आम तौर पर इस समय तक देश के दो-तिहाई हिस्सों में मॉनसून आ जाता है, किंतु अभी इसकी पहुंच 10-15 फीसदी इलाकों तक ही हो सकी है और यह 15 दिनों की देरी से गतिमान है. एक जून से अब तक देशभर में औसतन 44 फीसदी बारिश कम हुई है और महीने के आखिर तक यह आंकड़ा 40 फीसदी के आस-पास रहने की आशंका है. मॉनसून-पूर्व बारिश में कमी, सूखते जलाशय और करीब आधे देश में सूखे की स्थिति के बाद मॉनसून का इस हद तक कमजोर होना ढाई ट्रिलियन डॉलर की हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बेहद निराशाजनक है. सालाना बारिश में जून और सितंबर के बीच बरसनेवाले पानी का हिस्सा लगभग 70 फीसदी होता है. इस कमी का सीधा असर खरीफ की बुवाई पर पड़ा है. कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 14 जून तक 8.22 मिलियन हेक्टेयर रकबे में बुवाई हुई है, जो इसी अवधि में पिछले साल के आंकड़े से नौ फीसदी कम है. हालांकि, इस हालत में सुधार की गुंजाइश है, पर फसलों की बुवाई के दिन बहुत सीमित होते हैं और उसके बाद भी उन्हें पानी की दरकार होती है. जलाशयों और नहरों में पानी की कमी के कारण सिंचित क्षेत्रों में भी अनिश्चितता बनी हुई है तथा असिंचित रकबा तो मॉनसून पर निर्भर है ही. इस महीने की 13 तारीख तक जलाशयों में कुल क्षमता का 18 फीसदी पानी ही बचा हुआ था. इस संबंध में एक चिंता खाद्यान्न और सब्जियों की कीमत को लेकर है, लेकिन खाद्य मुद्रास्फीति के निम्न स्तर पर रहने के कारण ऐसा होने की संभावना नहीं है. परंतु फसलों के कम उत्पादन से किसानों की आमदनी घट सकती है. इससे कृषि संकट बढ़ सकता है और ग्रामीण क्षेत्रों में मांग में कमी आ सकती है, जिससे अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है. हालांकि, देश के सकल घरेलू उत्पादन में खेती का योगदान लगातार कम हो रहा है, किंतु आज भी इस पर आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा सीधे या परोक्ष तौर पर निर्भर करता है. वाहन, उपभोक्ता वस्तु, सीमेंट, ट्रैक्टर एवं किसानी के उपकरण आदि औद्योगिक उत्पादन के अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्र ग्रामीण और कस्बाई बाजार में मांग बढ़ने की उम्मीद लगाये बैठे हैं. बीते कुछ महीनों के आंकड़ों के अनुसार, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इन सभी वस्तुओं की मांग घट रही है. घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कारणों से अर्थव्यवस्था की बढ़त पहले से ही कुछ नरम है. सूखे और जल-संकट के कारण अनेक इलाकों से बड़े स्तर पर लोगों का पलायन हो रहा है. इससे शहरी संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा तथा ऐसे लोगों के लिए रोजगार जुटाने की समस्या भी पैदा होगी. तेज गर्मी और पेयजल के अभाव से सामान्य आर्थिक गतिविधियों पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है. हालांकि, केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने राज्यों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है, पर युद्धस्तर पर प्रयासों की दरकार है.

केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने राज्यों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है, पर युद्धस्तर पर प्रयासों की दरकार है.

कूटनीतिक दृढ़ता पर कायम रहें

पवन के वर्मा
लेखक एवं पूर्व प्रशासक
pavankvarma1953@gmail.com

क्या भारत को पाकिस्तान से वार्ता करनी चाहिए? पारंपरिक मत तो यह रहा है कि जब तक वह दहशतगर्दी को संरक्षण देना जारी रखता है, हमें बातचीत से दूर ही रहना चाहिए. ऐसा लगता है कि अभी हम इस नीति का ही अनुसरण कर रहे हैं. पाकिस्तान को पीएम नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने को नहीं बुलाया गया. हमने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा वार्ता आरंभ करने के संदेश की भी अनदेखी ही की. शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भाग लेने बिश्केक की अपनी यात्रा के दौरान मोदी ने पाकिस्तान द्वारा अपनी जमीन के ऊपर से होकर उनके विमान को उड़ने देने की पेशकश स्वीकार न की. फिर उस बैठक के दौरान भी उन दोनों के बीच कोई औपचारिक अथवा अनौपचारिक मुलाकात नहीं ही हुई. हालिया पुलवामा हमले सहित भारत पर लगातार किये जा रहे आतंकी हमलों में पाकिस्तान की प्रमाणित संलिप्तता के मद्देनजर हमारा यह कड़ा रवैया सही है. पूरे पाकिस्तान तक यह संदेश पहुंचना ही चाहिए कि बातचीत और दहशतगर्दी सहचरी नहीं हो सकतीं. पाकिस्तान ने अवश्य ही यह उम्मीद बांध रखी होगी कि पूर्व की ही भांति भारत एक बार फिर माफ करो और भूल जाओ की नीति पर चलते हुए सामान्य स्थिति की बहाली स्वीकार कर लेगा. ऐसी नरम नीति पाकिस्तान को इस हेतु और ढीठ ही बनाती है कि वह 'हिंसक हमलों के बाद रणनीतिक तुष्टीकरण' की अपनी सोची-समझी नीति बेरोक जारी रखे. हमारे द्वारा अपने कड़े रुख पर कायम रहने से ही इस धूर्त चाल की हवा निकल सकती है.

यहां तक तो यह सही है, पर क्या इन दो पड़ोसी देशों के नेताओं द्वारा किसी बैठक में साथ होने के समय भी अपने पारस्परिक व्यवहार से अपना वैमनस्य ही प्रदर्शित करना चाहिए? शंघाई सहयोग संगठन की उक्त बैठक में पुतिन एवं शी जिनपिंग समेत दर्जन भर अन्य नेताओं की नजरों के सामने इमरान खान और नरेंद्र मोदी ने एक दूसरे का अभिवादन तक नहीं किया. किसी भी संरचित वार्ता अथवा पूर्वनियोजित औपचारिक या यहां तक कि अनौपचारिक शिखर बैठक के संबंध में हमारी यह नीति ठीक हो सकती है, मगर क्या हमारे द्वारा इसे इस सीमा तक ले जाना उचित है कि दो धुर विरोधियों के मध्य मान्य एवं स्थापित बुनियादी शिष्टाचार का पालन भी नहीं किया जाये?

मुद्दे की बात यह है कि राजनय का अर्थ ऐसे किसी व्यवहार की बजाय वैचारिक नीति निर्माण होता है. बातचीत की जाये या नहीं, यह एक ऐसा फैसला है, जिसके सभी दीर्घावधि एवं अल्पावधि नतीजों पर विचार कर उनका पूर्वानुमान करते हुए उसे एक रणनीतिक ढांचे में स्थित किया जाना चाहिए और इस प्रक्रिया में हमारे राष्ट्रीय हितों को ही हमारा एकमात्र विनिर्देशक होना चाहिए. यदि वार्ता से हमारा राष्ट्रीय हित सधता हो, तो हमें वार्ता करनी चाहिए और यदि वह नहीं सधता हो, तो नहीं करनी चाहिए. पर इस संबंध में कोई भी निर्णय दोनों दिशाओं के एक सिलसिलेवार, निर्मम तथा भावनाविहीन विश्लेषण द्वारा ही लिया जाना चाहिए.

चाणक्य की राजनीति की मेरी समझ के अनुसार वार्ता अथवा अवार्ता अपने आप में कोई साध्य नहीं, सिर्फ किसी साध्य के साधन हैं और वह साध्य राष्ट्रीय हित है. चाणक्य ने स्वयं ही विभिन्न नीतिगत विकल्पों के एक मिश्रण को तरजीह दी, जिसका सार साम, दाम, दंड और भेद की उनकी सुप्रसिद्ध नीति में समाहित है. पांचवां परंतु कम जाना-माना नीतिगत विकल्प 'आसन' भी है, जिसका तात्पर्य 'सीमारेखा पर बैठे रहने की सोची-समझी रणनीतिक नीति' है. इन विकल्पों से एक सुविचारित सामरिक योजना के अंशगत रूप में किसी एक अथवा कई नीतियों के सम्मिलित चयन तथा इस्तेमाल की कला ही प्रबुद्ध विदेश नीति कहलाती है. बालाकोट पर हमारा हवाई हमला दंड का एक उत्तम उदाहरण था. पाकिस्तान द्वारा बातचीत की पेशकश पर हमारा मौन भी उसी नीति का सातत्य है.

हम इसके लिए भी तैयार रहें कि यदि पाकिस्तान हमारी शर्तों पर वार्ता को राजी होता है, तो यह वार्ता दहशतगर्दी के प्राथमिक एजेंडे से बहके नहीं, न ही उसके दायरे में अनचाहे अन्य मुद्दे भी शामिल हो जायें.

क्या हम हमेशा ही दंड की नीति पर बने रह सकते हैं? सीमापार से पुलवामा जैसे बड़े आतंकी हमले पर हर बार बालाकोट जैसे ही प्रत्युत्तर देने के आशय में हां. पर, प्रत्येक परिस्थिति और अवसर पर पाकिस्तान से अछूत की तरह व्यवहार करना दंड के प्रभाव को न्यून करने के अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उसको इसका श्रेय भी दिलायेगा कि वह भारत से अच्छे संबंधों का आकांक्षी है. हमें यह भी समझना चाहिए कि दो परमाणु शक्तिसंपन्न पड़ोसी देशों द्वारा हमेशा ही उग्र बने रहना विश्व को विचलित किये रखता है.

हमारी एक वांछित नीति तो यह हो सकती है कि हम अपनी पसंद के वक्त पर अपनी ही शर्त और एजेंडे पर वार्ता में भाग लें और इस एजेंडे में शीर्ष पर दहशतगर्दी हो. इससे विश्व को यह संदेश जायेगा कि भारत बेहतर संबंधों के लिए राजी तो है, मगर अपनी शर्तों पर, जो दहशतगर्दी के संरक्षण में पाकिस्तानी रिकॉर्ड को देखते हुए उचित होगा. हम इसी नीति को अपनायें और इस पर कायम रहें, ताकि पाकिस्तान को इस विषय में कोई भ्रम न रहे. हम इसके लिए भी तैयार रहें कि यदि पाकिस्तान हमारी शर्तों पर वार्ता को राजी होता है, तो यह वार्ता दहशतगर्दी के प्राथमिक एजेंडे से बहके नहीं, न ही उसके दायरे में अनचाहे अन्य मुद्दे भी शामिल हो जायें.

इसके साथ ही, उपयुक्त समय पर हमें पाकिस्तान में उपयुक्त वार्ताकारों के साथ द्विमार्गी कूटनीति अथवा पृष्ठभौमिक माध्यम की बातचीत की रणनीतिक उपयोगिता पर भी विचार करना चाहिए, जो फौज तथा आइएसआइ समेत पाकिस्तानी सियासत के अंदरूनी गठजोड़ के साथ होगी. पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बड़ी मुश्किल में पड़ी है. साम की रणनीति के तहत वहां के उन वर्गों तक सुनियोजित पहुंच बनानी होगी, जिन्हें अमन से फायदा होगा. इसके अलावा, पाकिस्तान को अकेला करने की कूटनीतिक कोशिशें तो जारी रहनी ही चाहिए, जैसा पीएम मोदी ने बिश्केक में यकीनन किया.

हमें बस तदर्थवाद या रणनीतिक सातत्य के अभाव से बचे रहना होगा. चाणक्य ने हमें सिखाया कि भावना और रणनीतिक नियोजन, संवेगात्मक प्रतिक्रिया एवं दीर्घावधि योजना निर्माण तेल और पानी के ही सदृश हैं, जो आपस में कभी भी समरूप नहीं मिल सकते. मगर इस बीच, अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में हमें पाकिस्तानी नेताओं के साथ सामान्य शिष्टाचार भी नहीं छोड़ने चाहिए. कूटनीति दृढ़ता का समर्थन तो करती है, पर आवश्यक सामाजिक गरिमा के अभाव का नहीं.

(अनुवाद : विजय नंदन)

बोधि वृक्ष

आध्यात्मिकता

आध्यात्मिकता का मतलब किसी खास तरह का अभ्यास करना नहीं है. यह आपके अस्तित्व के होने का एक निश्चित तरीका है. उस स्थिति तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है. यह आपके घर के बगीचे की तरह है. अगर मिट्टी, सूर्य का प्रकाश और पौधे का तना एक निश्चित स्थिति में हैं, तो यह फूल नहीं देगा, आपको इसके लिए कुछ करना होगा. आपको कुछ खास बातों पर ध्यान देना होगा. अगर आप अपने शरीर, मन, भावों तथा ऊर्जा को परिपक्वता के एक निश्चित स्तर तक ले जायेंगे, तो आपके भीतर कुछ और खिल उठेगा- यही आध्यात्मिकता है. जब आपकी तार्किकता अपरिपक्व होती है, तो यह हर वस्तु पर संदेह करती है. जब आपकी तर्कबुद्धि ऐसा अनुभव कर पाता है, जो उसे खुद से बड़ा लगे, तो वह उसे भगवान समझने लगता है. 'भगवान' को लेकर सारी सोच यही है कि कुछ भी जो आपसे बड़ा हो. यह कोई इंसान या फिर प्रकृति का कोई आयाम भी हो सकता है. परंतु क्या यही आध्यात्मिकता है? नहीं, यह केवल जीवन है. जब मैं कहता हूं, 'केवल जीवन', तो मैं इसे छोटी बात कहकर, टालने का प्रयास नहीं कर रहा. यह सबसे बड़ी चीज है. जब जीवन आपके लिए अभिभूत कर देनेवाला, एक शक्तिशाली और आनंददायी अनुभव हो जाता है, तब आप जानना चाहते हैं कि इसे किसने रचा होगा. अगर आप सृष्टि के स्रोत या प्रक्रिया को जानना चाहते हैं, तो आपके लिए सृष्टि का सबसे अंतरंग हिस्सा तो आपका अपना शरीर है. इसमें फंसी हुआ एक सृष्टि है. आपको उसे भूलना नहीं चाहिए. अगर आप जानते हैं कि सृष्टि का वह स्रोत आपके भीतर छिपा है, तो आप आध्यात्मिक हैं. आध्यात्मिकता परिपक्व हो जाती है, तो यह हर चीज को एक अलग ही प्रकाश में देखती है. किसी सागर या पर्वत पर जाना एक खूबसूरत अनुभव हो सकता है, आपको इस संसार का आनंद लेना भी चाहिए, पर इसके साथ ही यह भी समझना जरूरी है कि सागर में रहनेवाली मछली इसे एक आध्यात्मिक अनुभव नहीं मानती.

सद्गुरु जग्गी वासुदेव

पानी बचायें या मिट जायें

संजय बारू
द एक्सीडेंटल प्राइममिनिस्टर के लेखक
sanjayabaru@gmail.com

अभी जहां एक ओर भारत के पश्चिमी तट पर मॉनसून की तेज बौछारें पड़ रही हैं, वहीं दूसरी ओर ऐसी रिपोर्टें भी मिल रही हैं कि देश का 40 प्रतिशत से भी ज्यादा हिस्सा सुखाड़ की चपेट में है. देश के अलग-अलग हिस्सों में एक ही साथ बाढ़ और सुखाड़ दोनों की विभीषिकाओं से निबटना सरकार के लिए एक प्रतिवर्ष आनेवाली चुनौती ही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 'जल शक्ति' के लिए एक कैबिनेट स्तर के मंत्री की नियुक्ति के निर्णय की खबर जिस सप्ताह आयी, ठीक उसी सप्ताह यह रिपोर्ट भी मिली कि दिल्ली समेत 21 भारतीय शहरों में वर्ष 2020 तक भूजल समाप्त हो चुका होगा, जिसके असर को उन शहरों में बसनेवाले लगभग 10 करोड़ लोग झेलेंगे.

इस पृष्ठभूमि में जल उपयोग संबंधी जागरूकता स्तर को ऊपर उठाने की किसी भी कोशिश का स्वागत किया जाना चाहिए. इसलिए जब गुरुग्राम के स्थानीय अधिकारियों ने विराट कोहली द्वारा पेयजल से अपनी कार धोये जाने पर आर्थिक दंड लगाने का फैसला किया, तो मैं इस कदम के लिए उन अधिकारियों को तहे दिल से साधुवाद देना चाहता हूं. अफसोस सिर्फ इसका है कि यह दंड महज पांच सौ रुपयों की एक स्वल्प राशि का ही था.

हालांकि, आज से कई दशक पूर्व पानी इतना दुर्लभ नहीं था, फिर भी हमारी पीढ़ी के लोग जल उपयोग की अधिक चेतना के साथ बड़े हुए. जिस तरह हम लोगों को यह सिखाया गया कि कमरे से निकलते वक्त कमरे की बत्तियों तथा पंखे आदि को स्विच ऑफ कर दें, उसी तरह यह भी बताया गया था कि हम पानी को किफायत से खर्च करें और उसे व्यर्थ बरबाद न किया करें. बाल्टी से स्नान करना इसी उद्देश्य की पूर्ति का एक तरीका था. मगर आज, बाल्टी की बजाय शावर (झरने) से स्नान करने का चलन लोकप्रिय हो चुका है और समृद्ध घरों में तो पश्चिमी शैली के बाथटबों का प्रचलन भी तेजी से बढ़ा है.

बाल्टी-मग से स्नान करने के भारतीय चलन को तब एक दिलचस्प यूरोपीय समर्थन भी हासिल हुआ, जब मशहूर यूरोपीय पत्रकार विक्टर जोर्जा ने 'मेनचेस्टर गार्डियन' एवं 'ल मांद' जैसे सुप्रसिद्ध समाचार पत्रों के अपने लोकप्रिय स्तंभों में बाल्टी और मग से नहाने के अपने अनुभव को अपने पाठकों के साथ साझा किये. जैसा मुझे याद आ रहा है, तब विक्टर जोर्जा ने इस स्नान का वर्णन इन शब्दों में किया था- 'अपने हाथ में एक मग लें और उससे बाल्टी से जल निकाल पहले अपने बायें कंधे पर और फिर दायें कंधे पर तथा फिर यदि आपकी मर्जी हो, तो अपने सिर पर भी डालें. उसके बाद, अपनी छाती और पीठ पर तथा एक-दो मग पानी दोनों पैरों पर भी उड़ेलें. तत्पश्चात बदन पर साबुन मलें और एक बार फिर मग से पानी डालने की क्रिया दुहरायें. इस तरह, एक बाल्टी पानी से शरीर की अच्छी धुलाई हो जाती है.' विक्टर जोर्जा ने टब से स्नान के आदी अपने यूरोपीय पाठकों को यह बताया.

यदि शहरी भारत सिंगापुर से कोई एक सबक ले सकता है, तो वह पानी का संरक्षण तथा उसका पुनरुपयोग है. पिछले दो दशकों के दौरान इस शहर-राज्य की आबादी कई गुनी बढ़ चुकी है, फिर भी वह अपने सभी नागरिकों को पेय जल की पर्याप्त आपूर्ति कर पाने में सक्षम है. इस संबंध में सिंगापुर जितनी भी चीजें करता है, उनमें से भारत में सर्वाधिक किये जाने योग्य वर्षा जल संचयन है. पानी की कमी का जीवन पर क्या असर हो सकता है, हमारे देश के सामने इसका जीता-जागता उदाहरण फतेहपुर सीकरी है, जिसकी कहानी प्रत्येक वैसे शहरी भारतीय द्वारा याद रखे जाने योग्य है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी की बचत एक घर हासिल करने में लगा दी हो.

तालाबों को पुनरुज्जीवन देकर भूजल स्तर के पुनर्नवीकरण के कार्य पर नीति निर्धारकों द्वारा पिछले कुछ समय से गौर किया जा रहा है, मगर इस कार्यक्रम को पूरे देश में मिशन स्तर पर लागू करने हेतु इससे कहीं और ज्यादा कुछ किये जाने की जरूरत है.

तालाबों को पुनरुज्जीवन देकर भूजल स्तर के पुनर्नवीकरण के कार्य पर नीति निर्धारकों द्वारा पिछले कुछ समय से गौर किया जा रहा है, मगर इस कार्यक्रम को पूरे देश में मिशन स्तर पर लागू करने हेतु इससे कहीं और ज्यादा कुछ किये जाने की जरूरत है. यह उम्मीद की जानी चाहिए कि नये जलशक्ति मंत्री अपने पूर्ववर्ती की अपेक्षा बेहतर ढंग से इस चुनौती का सामना कर सकेंगे.

जल प्रबंधन के क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निर्वाह हेतु सरकार की जरूरत इस उपमहाद्वीपीय पारिस्थितिकी की प्रकृति में ही समाहित है. इतिहासकार कार्ल विटफोगल का 'चलित-जल समाज' (हाइड्रोलिक सोसाइटीज) का सिद्धांत मशहूर है, जिसके अनुसार ऐसी किसी भी संस्कृति में, जिसकी कृषि व्यवस्था बड़े पैमाने की सिंचाई प्रणाली पर निर्भर है, उसके लिए जरूरी संसाधन जुटाने हेतु राज्य सत्ता की आवश्यकता होती है.

भारत में भी राज्य सत्ता बड़ी सिंचाई प्रणालियों एवं तालाबों के निर्माण तथा उनके रख-रखाव के प्रबंधन द्वारा अपनी इस भूमिका का निर्वाह करती आयी है. इसी तरह, वर्तमान में वर्षा जल संचयन में भी सरकार के हस्तक्षेप की जरूरत है. मगर इन सबसे अधिक, आज सरकार के लिए जरूरत इस बात की है कि वह जल संकट के संबंध में जन जागरूकता पैदा करे. पेय जल को उसके सर्वथा अनुपयुक्त कार्य में व्यर्थ बहाने के लिए विराट कोहली पर आर्थिक दंड लगाना सरकारी हस्तक्षेप की एक प्रशंसनीय मिसाल है.

आपके पत्र

अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा की योजनाओं का स्वागत

प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुसलमानों की तरक्की के लिए जरूरी चीज शिक्षा और स्कॉलरशिप के लिए नयी योजनाओं को शुरू किया है. उनके इस पहल का हम तहेदिल से स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनकी इस योजना को जमीनी स्तर पर लागू किया जायेगा और पूरा काम किया जायेगा. देश में जो अभी मौजूदा हालात हैं, उस पर मुसलमानों का विश्वास होना और सुरक्षित महसूस करना बेहद जरूरी है. इसके लिए जरूरी है कि समाज में नफरत की जगह भाईचारगी और मुहब्बत बनी रहे और सबको साथ लेकर विकास की ओर मिलकर बढ़ें. साथ ही एक ऐसी मुहिम चलाया जाये जिससे देश में नफरत की राजनीति कम हो और अमन फैले. सच्चर कमेटी के सुझावों को लागू करने और अल्पसंख्यकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने की पहल हो तभी देश का विकास हो पायेगा.

मो इब्राहीम हुसैन, कांके, रांची

चमकी बुखार का कहर

बिहार में खासकर मुजफ्फरपुर में एक रहस्यमयी बीमारी ने कई माता-पिता से उनके कलेजे के टुकड़े को सदा के लिए छीन लिया है. सबसे दुखद है कि यह सिलसिला बदस्तूर जारी है. लोग इस रहस्यमयी बीमारी को चमकी बुखार कह रहे हैं, तो डॉक्टरों ने इसे एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिन्ड्रोम यानी एइएस का नाम दिया है. डराने के लिए इसका नाम ही काफी है. इस समय आइएमए, प्रशासन, सरकार और उनका आयुष मंत्रालय इस बीमारी के अचूक इलाज पर अपनी सक्रियता दिखाने में असमर्थ प्रतीत हो रहा है. अभी भी प्रशासन और सरकार अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर को ही ठीक करने में असमर्थ लग रही है. बीमारी के कारण और निवारण पर कोई रिसर्च और परिणाम नहीं निकल कर आ रहे हैं. क्या यही हमारी चिकित्सा जगत की सफलता है? क्या हमारी सरकार और ईश्वर का दर्जा पानेवाले डॉक्टर इन मासूमों को यूं ही काल का ग्रास बनने देंगे?

देवेश कुमार 'देव', गिरिडीह

हजारीबाग में विद्युत आपूर्ति

हजारीबाग शहर के लोग इन दिनों विद्युत आपूर्ति के लगातार बाधित रहने से बुरी तरह से परेशान हैं. इस प्रचंड गर्मी में पूरे दिन पूरी रात बिजली के नहीं रहने से विशेष रूप से गांधी नगर पूरब के निवासी बुरी तरह परेशान हैं. बिजली विभाग द्वारा केबल कार्य के आड़ में कई घंटे तक बिजली काट दिया जाता है. इस झुलसती गर्मी में बिजली का कटना मृत्युतुल्य कष्ट के बराबर है. गर्मी से राहत पाने के सारे उपकरण बिजली से ही चलते हैं और अगर बिजली लगातार सुबह से शाम तक कटी रहे और फिर रात में भी क्षणिक रूप से आये, तो स्थिति का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है. शिकायत करने पर भी विद्युत विभाग के अभियंता ध्यान नहीं देते और स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है. माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र आग्रह है कि विकास के इस दौर में हमें बिजली संकट से मुक्ति दिलवाएं

अनिल मिश्र, हजारीबाग

कुछ अलग

हरियाली का प्रबंधन जरूरी

क्षमा शर्मा
वरिष्ठ पत्रकार
kshamasharma1@gmail.com

पिछले दिनों अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर पेड़, पानी बचाने की खूब चर्चा हुई. हाल ही में किसी ने फेसबुक पर लिखा कि दुनिया के लाखों पेड़ गिलहरियों की देन हैं, क्योंकि ये खाने के लिए बीज छिपाकर रखती हैं और भूल जाती हैं. इसलिए किसी ने सुझाव दिया कि जो फल खाते हैं, उनके बीज बचाकर रखें. कभी यात्रा पर जायें, तो इन्हें रेलवे पटरियों और सड़क के किनारे बिखेर दें. इनसे कुछ दिन में पौधे उग जायेंगे और हरियाली बढ़ेगी.

पेड़ों में भी जीवन होता है, वे भी प्यार भरे स्पर्श को पहचानते हैं. जब कोई कुल्हाड़ा लेकर उनकी तरफ बढ़ता है, तो पेड़ कांपते हैं. इस खतरे का संकेत दूसरे पेड़ों को भी दे देते हैं. यही नहीं, कई बार जो व्यक्ति पेड़ को लगाता है, पालता-पोसता है, तो उसकी मौत पर वे पेड़ रातों-रात मर जाते हैं.

दिल्ली की एक मित्र के पिता ने घर में बड़े कागजी नींबू का पेड़ लगाया था. पेड़ पूरा फलों से भर गया था. एक शाम हृदय गति रुक जाने से उनकी मृत्यु हो गयी. आश्चर्य की बात यह कि अगले चौबीस घंटे में पेड़ के पत्ते पीले पड़ गये और सभी फल सड़ गये. यह मेरी आंखों देखी बात है.

अभी एक फोटो देख रही थी, जिसमें सड़क के किनारे लगे सभी पेड़ काटे जा चुके हैं. उनके विशालकाय तनों के अवशेष बचे हैं. कहां तो सड़क किनारे ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की बातें हो रही हैं और कहां इस तरह से पेड़ों को काटना कि उनका नामोनिशान न बचे. वैसे भी बड़े छायादार वृक्ष बेहद उपयोगी होते हैं. वे मनुष्य को न केवल ऑक्सीजन देते हैं, बल्कि कई औषधियों में भी काम आते हैं.

पेड़ों, नदियों, तमाम जल स्रोतों की चिंता तो हम खूब करते हैं, लेकिन खुद पर जब यह जिम्मेदारी आती है, तो बचने के लिए तरह-तरह के तर्क ढूंढ़ते हैं कि अरे जिंदगी की भाग-दौड़ में इतना समय कहां है कि इन बातों के बारे में सोचें. लेकिन हमारा जो इको सिस्टम है, जीवन की जो शृंखला है, उसमें हर एक की जगह है. इस शृंखला में अगर कोई एक आंकड़ा, कोई जीव-जंतु, पेड़-पौधे, नदी-पहाड़ गायब होते हैं, तो उसका असर हमारे जीवन की गतिविधियों पर पड़ता है. इसीलिए जब बेतहाशा गरमी हो, तब हमें पेड़ याद आयें या सूखते जल स्रोत चिंता पैदा करें, यह ठीक बात नहीं.

यदि पानी बचाने की चिंता करनी हो, तो बारिश के दिनों में अधिक से अधिक पानी बचाने का काम जिस तरह से भी हो सके, घर में, बाहर, तालाब, कुएं आदि में करें. अगर ऐसा हम करेंगे, तभी उसकी उपयोगिता पता चलेगी और आगे के लिए भी प्रेरणा मिलेगी. कैसे अपने आसपास हरियाली का प्रबंधन किया जा सकता है, छोटे-बड़े किसी भी रूप में, हमें यह सीखना चाहिए. उम्मीद सिर्फ दूसरों से न हो. हम भी कुछ करें. कुछ नहीं, तो अपने देश में बहुत से आदिवासी बहुल इलाकों से प्रेरणा ले सकते हैं, जहां पहले तो पेड़ ही नहीं काटे जाते. जरूरी होने पर पहले एक नया पेड़ लगाया जाता है, फिर जिस पेड़ को काटना हो, उसकी पूजा करके उससे माफी मांगी जाती है.

देश दुनिया से

हांगकांग प्रदर्शनकारियों के समर्थन में ताइवान

सरकार के प्रत्यर्पण बिल के खिलाफ हांगकांग में हुए दो बड़े विरोध प्रदर्शनों का ताइवान ने भी समर्थन किया है. वर्ष 1996 में ताइवान में हुए पहले प्रत्यक्ष राष्ट्रपति चुनाव के बाद से, द्वीप पर चीन-ताइवान संबंधों को लेकर बहस हावी रही है. बीते दो सप्ताह में हुए तीन बड़े प्रदर्शनों में सभी बीजिंग के साथ हांगकांग के रिश्तों से संबंधित हैं. हांगकांग में हुए इस घटनाक्रम से ताइवान के लोग भयभीत हो सकते हैं, जिन्होंने एक जुलाई, 1997 को हांगकांग को सौंपे जाने के बाद से वहां की स्वतंत्रता में कमी देखी है. ताइवानी डरे हुए हैं कि अगर वहां बीजिंग की शर्तों पर एकीकरण का दबाव बनाया जाता है, तो उनका हाल भी हांगकांग जैसा होगा. प्रत्यर्पण बिल का कानूनी पेशेवरों, शिक्षाविदों, छात्र कार्यकर्ताओं और व्यापारियों द्वारा व्यापक विरोध किया गया है. लाखों लोगों का प्रदर्शन चीन की न्यायिक प्रणाली के खिलाफ व्यापक अविश्वास दर्शाता है कि बीजिंग के वादे के बावजूद उनकी स्वतंत्रता में और कटौती की जायेगी. हांगकांग के प्रदर्शनकारियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए 16 जून को ताइवान में हजारों लोगों ने रैली की. और 17 जून को ताइवान की विधायिका ने हांगकांग के प्रदर्शनकारियों के समर्थन में संयुक्त बयान पारित किया.

South China Morning Post

कैरी हुआंग

कार्टून कोना

साभार : कार्टूनमूवमेंटडॉटकॉम

पोस्ट करें : प्रभात खबर, 15 पी, इंडस्ट्रियल एरिया, कोकर, रांची 834001, **फैक्स करें** : 0651-2544006,
मेल करें : eletter@prabhatkhabar.in पर ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है